उपसभापति: बैठ जाइये।

SHRI KARMA TOPDEN (Sikkim): Madam I have the highest regards for Mr. Sanjay Dalmia. He knows Sikkim well. And I am a bit disappointed that despite his knowledge of Sikkim he has taken instead brief from what has been written in the newspaper. Madam, I have just come from Sikkim. No Premier of Taiwan visited Sikkim. My name is mentioned also and it was said that the Premier of Taiwan was my personal guest. I wish he was a friend like that. I would not mind. But neither the Chief Minister of Sikkim nor I as the Minister of the State Government ever met any dignitary from Taiwan. No official reception was given to any dignitary of Taiwan. All that has been reported is ficticious. And may I take this opportunity to assure the House that I have just taken the oath to be loyal to the Constitution of India? And may 1 assure the hon. Member that we in Sikkim abide by the Constitution of India?

THE DEPUTY CHAIRMAN: We welcome you in the House, Mr. Topden.

श्री संजय डालमिया: राजस्थान, मैडम...**(व्यवधान)**

उपसभापति: राजस्थान का बाद में होगा। प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा।

Strike by Journalist and Non-working Journalists in Delhi

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभापति महोदया, आज दिल्ली में सभी अखबारों के जर्नलिस्ट्स और नॉन जर्नलिस्ट्स हड़ताल कर रहे हैं। उपसभापति जी, यह जो हड़ताल हो रही है वह जर्नलिस्ट्स के लिए जो नया वेज बोर्ड बनना है, जिसका मामला...**(व्यवधान)**

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): मैडम...**(व्यवधान)**

उपसभापति: आप जरा एक मिनट बैठिए। I Will permit you. Let Mr. Malhotra say something. Then I will allow you.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: उपसभापति जी, यह वेज बोर्ड का मामला काफी देर से पैंडिंग पड़ा हुआ है। प्रधान मंत्री जी ने 7 जनवरी को घोषणा की कि यह मामला फाइनल हो गया है। हम इसको लागू करने जा रहे हैं और कल उन्होंने यह कहा कि यह मामला कैबिनेट को तय करना है। तो कैबिनेट किसी दूसरे मुल्क की तो है नहीं, कैबिनेट अपने मुल्क की है और प्रधान मंत्री जी कैबिनेट में जब चाहें तय करवा सकते हैं। कल उन्होंने कहा है कि कैबिनेट के अंदर उसका फैसला करवाने के लिए, किसी और जगह पर उनको रेक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं और जहां पर कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी यह बात कही और प्रधान मंत्री जी ने कल भी इफ्तार पार्टी में कहा है कि मेरा क्या बिगड़ता है, बन जाए तो बन जाए। इस तरह इसको कोई इतना कैजुअली लेना मैं समझता हूं कि बहुत गलत है और यह नया वेज बोर्ड फौरी तौर पर बनाया जाना चाहिए। आज बजट आएगा और बजट कल अखबारों में छपेगा नहीं लोगों को बजट के बारे में पता नहीं लगेगा। सरकार को इस मामले को इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए। फौरी तौर पर नए वेज बोर्ड की घोषणा करनी चाहिए और उसका इंटरिम रिलीफ उनको देना चाहिए।

श्री ओ॰पी॰ कोहली (दिल्ली): उपसभापति महोदया, अभी प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जर्नलिस्ट्स और नॉन-जर्नलिस्ट्स के लिए वेज बोर्ड के गठन की बात कही। मैडम, यह मामला इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि आज जब बजट पेश किया जाएगा तो लोगों को और दिल्ली के लोगों को विशेष तौर से सिर्फ सरकार मीडिया के माध्यम से ही बजट पर और बजट पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का पता चलेगा मैडम पिछला वेज बोर्ड 1985 में गठित हुआ था।

उपसभापति: दिल्ली की एसेंबली में उठाइए न? दिल्ली की एसेंबली बन गयी है...**(व्यवधान)**...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, यह मामला सेंट्रल गवर्नमेंट को तय करना है, सेंट्रल कैबिनेट को तय करना है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: आप सब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Wage Board is to be decided by the Central Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am only reminding the Members that now we have the Delhi State Assembly.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: This matter has to be

decided by the Prime Minister or the Cabinet, not by Delhi's Chief Minister.

श्री ओ॰पी॰ कोहली: मैडम, यह सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। इस समय दिल्ली के पत्रकार हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के संगठनों ने अपने आंदोलन को इंटेंसीफाय करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की धमकी दी है। मैडम, पिछला वेज बोर्ड 1985 में गठित हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट 1989 में दी थी। मैडम, पांच वर्ष में वेज बोर्ड गठित होना चाहिए था, लेकिन आज हम 1994 में इसके गठन की बात कर रहे हैं। तो यह वेज बोर्ड कब गठित होगा और कब रिपोर्ट देगा और मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे सवाल पर सरकार का नजरिया कैजुअल है। वह क्या कहना चाहते हैं? जब सरकार ने स्वयं बार-बार यह कहा है कि हम जल्दी वेज बोर्ड गठित करेंगे तो मैं समझता हूं कि वेज बोर्ड गठित करने का कोई-न-कोई आश्वासन आज सदन में दिया जाना चाहिए। मैडम, इस मामले को और अधिक लटकाना ठीक नहीं है क्योंकि दिल्ली के लोगों तक यह सवाल सीमित नहीं है जैसाकि आप कह रही हैं।

उपसभापति: मैं नहीं कहा रही हूं। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं यह नहीं कह रही कि यह सीमित दिल्ली तक है।I was only reminding that now we have the Delhi State Assembly also and these issues can be taken up there.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: चौहान साहब, कहिए कि क्या कर रहे हैं? इसका वेज बोर्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे और अगर बनाएंगे तो कब तक बनाएंगे? .....**(व्यवधान)**....

श्री जे॰ पी॰ माथुर (उत्तर प्रदेश): मैडम, प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है कि हमारा क्या बिगड़ता है यानी अगर बजट नहीं छपेगा, तो नहीं छपेगा? यह धमकी है प्राइम मिनिस्टर की।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, होम मिनिस्टर बताएं कि क्या कर रहे हैं?

श्री जे॰ पी॰ माथुर: यह इनका एटीट्यूड है। पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं कि बिगाड़ लो क्या बिगाड़ते हो यह गलत है .....**(व्यवधान)**....

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have the constraint of time today.

श्री जे॰ पी॰ माथुर: यह बड़ी गंभीर बात है कि प्रधान मंत्री धमकी दें कि हमारा क्या बिगड़ता है, जो चाहे कर लो। प्रधान मंत्री को इतनी गैर-जिम्मेदारी की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री ओ॰ पी॰ कोहली: मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ने जैसे कहा कि इस मामले में फैसला कैबिनेट करेगी। तो कब तक कैबिनेट इस मामले में घोषणा करने वाली है?

Demand for bringing back the Indian gold placed with foreign banks

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): The House will remember that in 1991, at the initiative of the then Government—at the initiative of the Prime Minister at that time, Mr. Chandra Shekhar, or at the Finance Minister's initiative, I don't know—about 65 tonnes of India's gold, a sign of India's national honour, was placed with foreign financial institutions, particularly the Bank of England and the Swiss Bank, to raise loans to tide over the financial crisis that the country was facing at that point of time. The subsequent Government of Narasimha Raoji, and also the Finance Minister, Dr. Manmohan Singh, had as far as I remember, categorically assured the nation and also this House that as soon as our financial condition improved, this 'gold would be recovered and the national honour retrieved. That was a categorical assurance given to this House and to the nation. Unfortunately, Madam, I am given to understand that despite the so-called improvement in our foreign exchange reserves, as is being claimed by the Government on occasions, this quantity of gold has not been recovered and it is still left in the vaults of the Bank of England and Swiss Bank. The argument that is sought to be given is that the country is earning a three per cent interest. If the gold is kept in the vaults of the RBI, no interest is going to be earned but if it is kept with the Bank of England, there is going to be a three per cent earning by the country. This means the Government has violated its promise. This means gold is being kept at the cost of the national honour. I say 'national' honour because sale of gold is a sign of insolvency. Every person in the country knows that gold is a standard for measuring our national pride. Even